बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 178 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 15 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

संजय भंडारी से जुड़े पीएमएलए केस में रॉबर्ट वाड्रा की ईडी के सामने पेशी, प्रियंका भी साथ पहुंची

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचे। ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे वाड्रा के साथ प्रियंका भी थीं। वाड्रा सुबह 11 बजे पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि व्यवसायी का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया।एजेंसी ने पिछले महीने उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए दो बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा के कारण अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के तीन अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर रही है, जिनमें यह मामला भी शामिल है।

मानसून सत्र में पेश होगा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान

नई दिल्ली।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मांडविया ने यह जानकारी उस समय दी, जब वह नशा मुक्ति के खिलाफ युवा कार्य विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में बहुपक्षीय खेल आयोजनों में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा, विधेयक को आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। मैं कुछ दिनों में और जानकारी दूंगा यह विधेयक देश के खेल प्रशासकों के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। इसके तहत एक नियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देने और उन्हें फंडिंग प्रदान करने का अधिकार होगा। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सुशासन से जुड़ी शर्तों का कितना पालन करते हैं। यह बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेल महासंघ उच्चतम शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें। इसके अलावा, इस विधेयक के मसौदे में आचार संहिता आयोग और विवाद निवारण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है, ताकि खेलों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। इस विधेयक पर लंबे समय से बहस चल रही है। भारतीय ओलंपिक संघ

(आईओए) ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि उसका मानना है कि एक नियामक बोर्ड की स्थापना से उसकी राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुख निकाय के रूप में स्थिति कमजोर हो सकती है। मांडविया ने दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों में तनाव होने के बावजूद भारत में होने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी पर कोई रोक नहीं होगी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो गए हैं। अगले महीने बिहार में पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, नवंबर-दिसंबर में तमिलनाडु में एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप और सितंबर-अक्टूबर में नई दिल्ली में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप – इन आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी की उम्मीद है। मांडविया ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है। हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में खेलने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वह क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई और खेल। लेकिन जब बात द्विपक्षीय खेल आयोजनों की आती है, तो सरकार की स्थिति सभी को पता है। पाकिस्तान हॉकी संघ (पीएचएफ) ने भारत में होने वाले दो टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी सरकार से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इजाजत मिली है या नहीं। खेल मंत्री ने कहा, हमने पाकिस्तान से कहा है कि हम उन्हें एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए वीजा देंगे, लेकिन अब यह उनकी सरकार पर निर्भर करता है कि वह टीमें भेजती है या नहीं। हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, दोनों ही अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हैं और जो भी टीमें हिस्सा लेंगी, उन्हें समान व्यवहार मिलेगा। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होगा, जबकि जूनियर वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।

यमन में केरल की नर्स निमिषा की फांसी टलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म?

नई दिल्ली ।

यमन की जेल में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के बचने की उम्मीद धुंधली पड़ती दिख रही है. निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है और इधर भारत में केरल से दिल्ली तक उनके लिए आखिरी कोशिश चल रही है. बुधवार को इस मामले में उम्मीद की किरण धुंधली पड़ गई. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए सरकार और कुछ नहीं कर सकती. केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है... लेकिन हम क्या कर सकते हैं.

इसकी एक सीमा है. सरकार ने कहा कि निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि परिवार (यमनी व्यक्ति जिसकी मौत हुई) ब्लड मनी यानी वित्तीय मुआवजा को स्वीकार करने के लिए सहमत हो. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह बहुत जटिल मुद्दा है और ब्लड मनी का मामला निजी मामला है. भारत सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती. हमने जो भी संभव था, वह कोशिश की. हमने मामले के बारे में ज्यादा सार्वजनिक हुए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, इसकी एक सीमा होती है. जज ने पूछा कि क्या सरकार परिवार द्वारा जमा किए गए ब्लड मनी पर यमन से बातचीत करने का प्रयास कर सकती है. इसपर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि यह उनके हाथ में ज्यादा नहीं है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, रियाद का दूतावास इस मामले को संभालता है. हम बस चाहते हैं कि सरकार से कोई जाए और ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए परिवार से बात करे. हम अधिक राशि भी देने को तैयार है. पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया को 2020 में यमन के एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. वह उसका व्यापारिक साझेदार था. यह घटना जुलाई 2017 में घटी थी. पिछले साल नवंबर में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी थी और देश के सरकारी अभियोजक ने अब आदेश दिया है कि उसे मंगलवार 16 जुलाई को को फांसी दे दी जाए.

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, देशभर में हर हर महादेव की गूँज

नई दिल्ली शिवभक्तों के लिए सावन के सोमवार का दिन सबसे पावन माना जाता है। इस वर्ष के पहले सोमवार को देशभर में शिवालयों में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं शिवालयों में घंटों लंबी कतारें लगीं हैं तो कहीं कांवड़िये हर-हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरे देश में यह दिन शिवभक्ति के उत्सव में बदल गया है। हम आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तराखंड के केदारनाथ और झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे प्रमुख शिवधामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालु गंगा जल और अन्य पवित्र जल स्रोतों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचे। दिल्ली के प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर और मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। जगह-जगह भोलेनाथ के भजन, डमरू और घड़ियालों की ध्वनि से वातावरण गूंजता रहा। सावन के पहले सोमवार

के अवसर पर कांवड़ यात्रा ने विशेष रंग लिया। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से हजारों की संख्या में कांवड़िए पैदल यात्रा कर अपने-अपने शिवालयों में जल चढ़ाने पहुंचे। सड़कें भगवा रंग से सराबोर दिखीं, हर ओर बोल बम के नारे गूंज रहे थे। कांवड़ियों के स्वागत के लिए सहयोग शिविर, स्वास्थ्य केंद्र और भंडारे जगह-जगह लगे रहे। हम आपको बता दें कि जहां एक ओर भक्ति का उत्साह चरम पर रहा, वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। विशेष पुलिस बल, स्वास्थ्य टीम और आपातकालीन सेवाएं जगह-जगह तैनात रहीं। कई शहरों में ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से भीड़ की निगरानी की गई ताकि कोई अनहोनी न हो। हम आपको बता दें कि सावन का सोमवार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय समाज में आस्था, परंपरा और संस्कृति के सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। आज व्रत रखकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि से भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। कई जगह शिव बारात, भजन संध्या और कथा-प्रवचन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धा के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द का संदेश भी फैल रहा है। बहरहाल, सावन का पहला सोमवार भारत की सांस्कृतिक एकता, श्रद्धा और आस्था का जीवंत प्रमाण है। देश के कोने-कोने से उमड़ी यह भीड़ न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि आधुनिक समय में भी भारत की आध्यात्मिक परंपराएं कितनी मजबूत और जीवंत हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ सावन के इस सोमवार ने शिवभक्तों के मन में शांति, सुख और उत्साह भर दिया।

मध्य प्रदेश (सक्षम भारत) आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में नर्सिंग की कापियों के वैल्युवेशन ही वी एस सिस्टम में हो रहे नियम विरुद्ध वैल्यूएशन के भ्रष्टचार को लेकर प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा. छाया- सक्षम भारत रूप

दिल्ली हवाई अड्डे पर बारिश के बीच यात्रा परामर्श जारी, यात्रियों से मेट्रो का इस्तेमाल करने का आग्रह

नई दिल्ली । दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने एक यात्रा परामर्श जारी कर यात्रियों से राष्ट्रीय राजधानी में जारी बारिश के बीच हवाई अड्डे तक आने-जाने में होने वाली देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने को कहा है। यह सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब सोमवार सुबह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फिर से बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर और आसपास के इलाकों में दिन भर मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। डायल ने यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आने-जाने के लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करें, ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके। डायल की सलाह में कहा गया है, भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब रहने की संभावना है। हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे तक पहुँचने और संभावित देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो सहित परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर विचार करें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार, 14 जुलाई को दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। शहर में 15 जुलाई से 20 जुलाई तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। रविवार को शहर में पहले ही भारी बारिश हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जलभराव और यातायात जाम हो गया था। राजीव चौक जैसे प्रमुख चौराहों पर सड़कों के जलमग्न होने के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी होने से काफी भीड़भाड़ देखी गई। पिछले बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में भारी व्यवधान पैदा हो गया है, उत्तम नगर के बिंदापुर जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात ठप हो गया। अधिकारियों ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाने और मौसम व यातायात संबंधी सलाह से अपडेट रहने का आग्रह किया है।

निशिकांत दुबे ने परमाणु डिवाइस लापता होने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और हिमालय में नंदा देवी पर्वत के पास लापता अमेरिकी परमाणु उपकरण की भूमिका पर सवाल उठाया तथा इसे भारत में हाल की प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा। एक्स पर एक पोस्ट में, दुबे ने अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 1978 में लिखे गए एक पत्र की प्रति संलग्न की। इस पत्र में सीआईए के गुप्त अभियान और हिमालय में खोए हुए प्लूटोनियम-चालित उपकरण से संभावित रेडियोधर्मी रिसाव पर चिंता व्यक्त की गई थी। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के आगे नतमस्तक नेहरु गाँधी परिवार। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी और भारत के आस्था के साथ किसानों की तबाही। 1. क्या केदारनाथ का हादसा अमेरिका के न्यूक्लियर वस्तु के कारण हुआ जो नंदा देवी पर्वत शिखर के उपर से 1960 में गायब हो गया? 2. क्या तीस्ता नदी के बाढ़ का भी वही कारण है 3. गंगोत्री यमुनोत्री के पिघलते ग्लेशियर और गंगा के पानी में लगातार कमी किसानों की तबाही का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेहरु जी का सरेंडर है? उन्होंने आगे लिखा कि डूब मरो कांग्रेसी यह अमेरिका की सरकार का गोपनीय दस्तावेज है जो 2013-14 में जनता के सामने आया। 1. उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, असम में कैंसर, दमा, टीबी, डायबिटीज़ का जिम्मेदार नेहरु जी अमेरिका का समझौता है। 2. 1962 में नेहरु जी के साथ हिमालय पर न्यूक्लियर जेनेरेटर बैठने का समझौता हुआ। 3. 1963-65 में सीबीआई बनाने के बाद पहला मामला यही CIA के साथ अंजाम दिया।

4, न्यूक्लियर जेनेरेटर आज भी मौजूद जिसके कारण पूरा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत बर्बाद करने का बोझ कांग्रेस ने उठाया। भगवान रक्षा करें।

न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार, सिमी पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सिमी के प्रतिबंध को और पांच साल बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल न्यायाधिकरण ने अपने एक फैसले में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर और पांच साल तक और प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने, न्यायाधिकरण के 24 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने 29 जनवरी 2024 को सिमी पर और पांच साल प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया। सिमी को पहली बार साल 2001 में प्रतिबंधित घोषित किया गया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद से इस संगठन पर प्रतिबंध जारी है। सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी। जमीयत ए इस्लामी हिंद में विश्वास रखने वाले युवकों और छात्रों ने सिमी का गठन किया था। चुनाव चिन्ह विवाद पर शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। स्पीकर ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे गुट को देने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और अब इस पर असमंजस की स्थिति को जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने शिवसेना यूबीटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि हम मामले की सुनवाई अगस्त में तय कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में वे चाहते हैं कि मामले पर जल्द सुनवाई हो। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने जल्द सुनवाई का विरोध किया और कहा कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि वे जल्द सुनवाई नहीं कर सकते।

दिल्ली इमारत हादसा: 32 साल बाद भाई के घर गई थी राबिया, दो दिन बाद मौत, शहजाद बोला- वादा पूरे किए बिना चली गई

नई दिल्ली । बहन राबिया परवीन की मौत की खबर सुनकर दिल्ली पहुंचे शहजाद की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस यही कहे जा रहे हैं कि कुछ घंटे पहले ही बहन से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। बहन ने जल्द ही मिलने की बात की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसे हालात में बहन से मुलाकात होगी। एक रिश्तेदार का कॉल आया और उसने मकान गिरने की बात बताई। शहजाद उसी समय कोट कादर, नजीबाबाद, बिजनौर से दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचे तो बहन-बहनोई की मौत की खबर पता चली। यह भी पता चला कि परिवार के और भी लोग मलबे में दबे हैं। उनके सामने ही चार और लोगों के शव निकले। जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में शहजाद ने बताया कि पीलिया होने पर बहन ने जबरदस्ती दिल्ली बुला लिया। अपने घर पर रखकर उनका दो माह तक इलाज करवाया। छोटी सी बात पर वह कॉल करके पूछती थी। बकरीद के बाद उसने कॉल कर कोट कादर आने की बात की। शादी के 32 साल बाद पहली बार राबिया अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर आई थी। बहनोई मतलूब को छोड़कर पूरा परिवार 18 दिनों तक उनके घर पर रुका रहा। बुधवार को ही वह दिल्ली लौटी थी। इस बीच आफिया ने कॉल कर उन्हें जयपुर बुला लिया। परवेज के बेटे से मिलने की चाह में राबिया जयपुर भी न रुकी। शुक्रवार को ही बेटी से वापस जाने की बात कर वह दिल्ली पहुंच गई। देर रात वह अपने पोते अहमद के साथ खेली। इसके बाद वह बाकी परिजनों के साथ सो गई। सुबह सोते समय ही इमारत जमींदोज हो गई। राबिया उनके पति मतलूब, दो बेटे जावेद, अब्दुल्लाह, बेटी जूबिया और उसकी बेटी फौजिया की मौत हो गई।

केरल सरकार ने किया राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का विरोध

नई दिल्ली ।लंबित विधेयकों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिकाओं को केरल सरकार ने वापस लेने का अनुरोध किया। इसका केंद्र ने विरोध किया। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। केरल सरकार ने लंबित विधेयकों को मंजूरी न देने को लेकर केरल के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ के सामने केरल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में हाल ही में पारित निर्णय के मद्देनजर यह मुद्दा निरर्थक हो गया है। इसका अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को भेजे गए संदर्भ पर शीर्ष न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। मेहता ने कहा कि केरल सरकार की याचिका को भी राष्ट्रपति के संदर्भ के साथ संलग्न किया जा सकता है। इस पर केरल सरकार के वकील वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी याचिका का विरोध कैसे किया जा सकता है? राज्य सरकार के याचिका वापस लेने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है? इसके पीछे कोई तर्क तो होगा। इसका मतलब तो यही है कि दोनों पक्ष पैसे वसूलेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर देंगे कि मामले को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई। इससे पहले 22 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या तमिलनाडु की याचिका पर हाल ही में दिए गए फैसले में केरल सरकार ने अपनी याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को शामिल किया गया है? तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कार्रवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने आठ अप्रैल को राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने के फैसले को अवैध और कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 जुलाई को केरल की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी। जिसमें विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया था। केरल सरकार ने आरोप लगाया कि तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे और उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

मुद्दों की धार और नेताओं के तेज की कसौटी बनेगा बिहार चुनाव

ऑपरेशन सिंदूर की गर्मी अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान (एसआईआर) से पैदा हुआ विवाद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सड़क से लेकर मीडिया तक सियासी घमासान तेज हो गया है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के विशेष अभियान को लेकर विपक्ष सड़कों पर है और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की कवायद पर रोक लगाने के बजाय उसे सलाह दी है कि वह आधार कार्ड राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्रों को भी उन जरूरी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करे जो मतदाता सूची में नाम आने के लिए जरूरी हैं। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है, जबकि चुनाव आयोग मतदाता फॉर्म जमा करने का काम 25 जुलाई तक पूरा कर लेगा। अदालत के रुख को दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र में हर मुद्दे की कसौटी जनता का फैसला है और इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यानी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण का चुनाव आयोग का विशेष अभियान दोनों को बिहार की जनता की अदालत की कसौटी पर ही कसा जाएगा। बिहार चुनाव में क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों के अलावा जो ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, उनमें ये तीनों मुद्दे सबसे प्रमुख होंगे। पहलगाम में आतंकवादी हिंसा के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए भारतीय वायुसेना के हमलों और उसके बाद अचानक हुए संघर्ष विराम को देश के जनमानस ने किस रूप में लिया है बिहार चुनाव का नतीजा इसका संकेत होगा। क्योंकि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई निर्दोष पर्यटकों की हत्या के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जनसभा बिहार में ही की थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि इस हमले के दोषी दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी रूह कांपेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भाजपा और एनडीए, प्रधानमंत्री के इस संकल्प के पूरा होने का दावा कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस राजद वामदलों का महागठबंधन सेना की शानदार कामयाबी के बाद अचानक युद्धविराम क्यों हुआ और क्या भारत ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया जैसा कि दावा राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कर रहे हैं और इस लड़ाई में भारत का क्या नुकसान हुआ, इसी मुद्दे बना एक सत्ता पक्ष को घेरेंगे। जहां भाजपा जद(यू) लोजपा और हम के गठबंधन वाला सत्ताधारी एनडीए विपक्ष के आरोपों को पाकिस्तान की भाषा कह कर कठघरे में खड़ा करेगी, वहीं विपक्ष ट्रंप के बयानों, सिंगापुर में सीडीएस के बयान और इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के कैप्टन के बयान का हवाला देकर सरकार पर हमला करेगा। अब जनता दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोपों को कैसे लेती है इसका संकेत चुनाव नतीजे देंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान एसआईआर का है। ये ऐसा मुद्दा है जो अगर पूरे तरह अमल में आ गया तो भी चुनाव को प्रभावित करेगा और अगर अमल में नहीं आ सका तो भी इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। अमल में आने पर जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर होंगे, उन्हें लेकर विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाएगा और अगर अमल में कोई कमी रह गई तो विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करके उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगा। वहीं सत्ता पक्ष इस अभियान को फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों के खिलाफ एक शुद्धिकरण अभियान बताकर इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगा। अभी जब यह अभियान 25 जुलाई तक पूरा होने जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाने इनकार करते हुए मतदाताओं की पहचान के लिए मांगे जाने वाले 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को भी शामिल करने की सलाह चुनाव आयोग को दी है। अब ये चुनाव आयोग पर है कि वह इन्हें शामिल करता है या नहीं। अगर आयोग ने इन्हें शामिल कर लिया तो काफी हद तक विपक्ष का यह आरोप कि इस अभियान से करीब पौने दो करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे जो उनके मताधिकार की खुली अवहेलना होगी, भोथरा हो जाएगा बल्कि तब यादा लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका भी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर सकता है।

लेकिन अगर चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना तो विपक्ष उसकी सत्तापक्ष से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय के अपमान का भी मुद्दा बनाएगा। इसे भी बिहार की जनता किस रूप में लेगी इसका पता चुनाव नतीजों से ही लगेगा। क्या चुनाव आयोग का विशेष अभियान बिहार में मतदाताओं के कथित फर्जीवाड़े को रोककर पारदर्शी चुनाव कराएगा जिसका फायदा क्या सत्ता पक्ष को मिल सकता है या इसे लेकर होने वाली परेशानी बिहार के गरीब और वंचित वर्ग को विपक्ष की तरफ आकर्षित करेगी। बिहार चुनाव का तीसरा बड़ा मुद्दा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर चलने वाली चर्चाओं के साथ ही उनकी उम्र और लंबी पारी भी एक मुद्दा है। नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। बीच के एक छोटे काल खंड को छोड़कर भाजपा उनके साथ सत्ता में साझीदार रही है। नीतीश कुमार और भाजपा हर चुनाव में लालू राज के जंगल राज की याद दिलाकर बिहार की जनता का भयादोहन करती रही है, लेकिन इधर जिस तरह बिहार में अचानक अपराधों हत्या लूट आदि में तेजी आई है और उसे लेकर खुद भाजपा के नेता तक परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो खुलकर कानून व्यवस्था पर चिंता जताने लगे हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पुलिस तंत्र को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और दूसरे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका दोष रेत माफिया और शराब माफिया पर मढ़ रहे हैं। उधर राजद ने कानून व्यवस्था को लेकर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाना भाजपा की मजबूरी भी है और समस्या भी। सरकार की हर नाकामी की जिम्मेदारी जद(यू) के साथ भाजपा की भी है और अगर राज्य की कानून व्यवस्था के यही हाल रहे तो इस बार के चुनाव में एनडीए पर जंगल राज वाला ब्रह्मास्त्र इस बार कमजोर हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है कि सीट बंटवारे में जद(यू) सौ से कम सीटें नहीं लड़ेगा और अगर उसके जीत का स्ट्राइक रेट पिछली बार से भी कम रह गया तो एनडीए को बहुमत का आंकड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा भी सौ से यादा सीटें नहीं लड़ पाएगी। बाकी 43 सीटें चिराग पासवान जीतनराम मांझी उपेंद्र कुशवाहा के दलों के बीच बटेंगी। ऐसे में अगर विधानसभा त्रिशंकु हो गई तो भले ही तोड़ फोड़ करके एनडीए सरकार बना ले, लेकिन यह उसकी नैतिक हार होगी। सवाल यह भी है कि चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में क्या एनडीए फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा या महाराष्ट्र की तरह चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन बाद में अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी। ये सारे सवाल विपक्ष की तरफ से एनडीए पर दागे जाने शुरू हो गए हैं और इन्हें लेकर फिलहाल भाजपा जद(यू) बचाव की मुद्रा में है। हालांकि, अभी चुनाव में तीन से चार महीने का समय है और एनडीए को प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से बड़ी उम्मीद है कि वह आखिर में बिहार का परिदृश्य बदल सकते हैं। वहीं विपक्ष राजद कांग्रेस वाम गठबंधन में भी तेजस्वी की आक्रामकता राहुल गांधी का सामाजिक न्याय और वाम दलों की संगठन की ताकत की भी परीक्षा होगी, क्योंकि जहां राजद ने तेजस्वी को अपना चेहरा घोषित कर रखा है।

ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, अपनी नीतियों व बयानों से सुर्खियों में रहे हैं

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी फर्स्ट, टैरिफ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,गैरकानूनी अप्रवासियों का मुद्दा सहित अनेकों वादे किए थे जिन्हें पूरा करने के लिए वह हद से अधिक स्पीड से भिड़ गए हैं, परंतु मैं जल्दबाजी से कोई भी काम करना हानिकारक हो सकता है, इसपर भारत में कई कहावतें हैं, जैसे जल्दबाजी का काम शैतानी कम, धैर्य रखो सहित अनेकों कहावतें है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे है क्योंकि ट्रंप जब से चुनकर आए है,अपने चुनावी वादे बहुत जल्दबाजी से लागू करने उमड़ पड़े है, जबकि मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं के किसी भी काम, वादों, उम्मीदों को पूरा करने धैर्य से व संकल्प के साथ रणनीतिक रूप से काम करने कीजरूरत है, ताकि उसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। मेरे विचार में शायद ट्रंप साहब इस जल्दबाजी में ही काम कर रहे हैं, जिसका सटीक उदाहरण यह है कि जिस तरह वह निर्णय लेकर फिर उन्हें स्थगित करना,या उल्टीमेटम देना एक बारगेनिंग नीति की ओर बढ़ रहे हैं, अमेरिकी पांच देशों के के साथ सम्मेलन में व्यवहार, अनेक आर्थिक मजबूत देशों से व्यवहार सहित अनेक मुद्दों पर दबावतंत्र व दादागिरी का आभास हो रहा है,कि पूरी दुनियाँ से एक तरह से दुश्मनी की ओर पग बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वह अपने घरेलू यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाकर, चीन पर 145 पर्सेंट टैक्स लगाकर फिर पीछे हटना, सभी को टैरिफ का अल्टीमेटम देकर दबाव बनाना उचित नहीं है, इस बात का संयुक्त वक्तव्य ब्रिक्स सम्मेलन में भी दिया गया था। चूंकि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं अपनी नीतियों, बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप के टैरिफ वार पर जग हंसाई- दुनियाँ से दुश्मनी की नौबत आई-नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चांस घटाई साथियों बात अगर हम 12 जुलाई 2025 को मैक्सिको व यूरोपीय यूनियन पर 30 पर्सेंट टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू करने की घोषणा करने की करें तो,उन्होंने इस संबंध में मैक्सिको और यूरोपीय संघ को लिखे पत्रों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करके जानकारी दी।ट्रंप के इस कदम से ट्रेड वॉर के और तेज होने की संभावना बढ़ गई है, खासकर ऐसे समय में जब यूरोपीय संघ अपने सहयोगी अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ को अब अमेरिकी बाजारों में भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ट्रंप की यह घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और ब्राजील से आने वाले सामानों पर टैरिफ में की गई बढ़ोतरी के बाद आई है।उन्होंने इन देशों से तांबे के आयात पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है।यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर कहा, यूरोपीय संघ के निर्यात पर 30 परसेंट टैरिफ अटलांटिक के दोनों ओर के व्यवसायों,उपभोक्ताओं और मरीजों को नुकसान पहुंचाएगा। हम 1 अगस्त तक समझौते की दिशा में काम करना जारी रखेंगे,साथ ही, हम 30 पर्सेंट टैरिफ के इस फैसले पर उचित प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने और यूरोपीय संघ के हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मजबूत संबंधों के बावजूद, अमेरिका ने मैक्सिको के फेंटेनल संकट से निपटने के लिए उस पर टैरिफ लगाया है, इसके बारे में कहा गया कि यह आंशिक तौर पर मैक्सिको की तरफ से कार्टेल्स को रोकने में असफलता के कारण है,ट्रंप के अनुसार, मैक्सिको मुझे बॉर्डर सुरक्षित करने में मदद कर रहा है,लेकिन इस देश ने जो किया है वह काफी नहीं है,मैक्सिको ने अभी तक उन कार्टेल्स को नहीं रोका है जो पूरे उत्तरी अमेरिका को नार्को-तस्करी के मैदान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

जाहिर है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन (ईयू) पर 30 फीसदी तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, इन देशों पर टैरिफ एक अगस्त से लागू हो जाएगा, इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका के सात छोटे व्यापारिक साझेदारों को टैरिफ की चिट्ठी भेजी है जिसमें फिलीपींस, ब्रुनेई, मोल्दोवा, अल्जीरिया, लीबिया, इराक और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।

साथियों बात अगर हम ब्राजील में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर ट्रंप के नाराजगी वाले बयान की करें तो,एक संयुक्त वक्तव्य में पीएमसहित ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि हम एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जो व्यापार को विकृत करते हैं और डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। बयान में «वैश्विक व्यापार में टैरिफ के बढ़ते उपयोग» का भी उल्लेख किया गया। हालांकि इस दौरान नाम नहीं लिया गया, लेकिन सभी जानते हैं कि बात अमेरिका की हो रही है।इसके अलावा ब्रिक्स के साझा बयान में चेतावनी दी गई कि टैरिफ के निरंतर 'अंधाधुंध' उपयोग से वैश्विक व्यापार कम हो सकता है।इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिससे मौजूदा आर्थिक असमानताएं और बढ़ सकती हैं। तेहरान अब इस संगठन का पूर्ण सदस्य है और यह अपरिहार्य था कि संयुक्त वक्तव्य में इजरायल के साथ सैन्य संघर्ष और अमेरिका द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी का उल्लेख किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ट्रंप ब्रिक्स को निशाना क्यों बना रहा है। इसको लेकर पश्चिम के अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक चाहे जो भी कहें, ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुट अपने समर्थक जुटा रहा है और अमेरिका तथा अन्य पारंपरिक शक्तियों के लिए चुनौती के रूप में उभर रहा है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पसंदीदा मुद्रा के रूप में डॉलर को हटाने की बात करने को बल1 दे रहा है।इसके अलावा नव-विकसित,विकासशील और अल्प-विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर इसके बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए सौदे करते समय शर्तें तय करना कठिन हो गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान तथा 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें शामिल होंगे। 6 महीने पहले ब्रिक्स करेंसी को लेकर जब समूह के देशों ने बड़ा ऐलान किया था, और डॉलर को चुनौती देने की बात कही थी, तो उस दौरान भी ट्रंप ने गुस्सा जाहिर किया था। ट्रंप ने कहा था कि ऐसे देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। एक तरफ ट्रंप धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी धमकियों से ब्रिक्स देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत होते नजर आ रहे हैं। साथियों बात अगर हम अमेरिकी विदेश विभाग के 1300 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की करें तो,अमेरिका में, संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के तहत, विदेश विभाग के 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अनैच्छिक रूप से की गई इस छंटनी में 1,107 सिविल सेवा और 246 विदेश सेवा के कर्मचारी शामिल हैं।इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यालय के लगभग सभी सिविल सेवा कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। संघीय सरकार के व्यापक पुनर्गठन प्रयास के तहत, इस साल की शुरुआत में 1,500 से ज्यादा विदेश विभाग के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी थी। यह छंटनी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ ही दिनों बाद हुई है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन की संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती की योजना आगे बढ़ सकती है।अमेरिका में संघीय सरकार में छंटनी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी छंटनी जारी रखने के पक्ष में फैसला सुनाया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप सचिव ने कहा कि जिन कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, उन्हें जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विदेश मंत्रालय से कितने लोगों को निकाला जाएगा। विदेश मंत्रालय ने मई में कांग्रेस को छंटनी और पुनर्गठन के बारे में सूचित किया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में कटौती की जाएगी। साथियों बात अगर हम अफ्रीकी देशों के तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में बैठक में ट्रंप द्वारा व्यवहार प्रिंसिपल का रोल अदा करने की करें तो,राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में अफ्रीका के 5 देशों के राष्ट्र-प्रमुखों के साथ तीन दिनों का शिखर सम्मेलन शुरू किया। ये 5 देश हैं, गैबॉन गिनी-बिसाऊ लाइबेरिया, मॉरिटानिया और सेनेगल। 9 जुलाई को इस मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रम्प किसी स्कूली बच्चों की क्लास में बैठे प्रिंसिपल की तरह बर्ताव करते रहे। उन्होंने सबसे पहले मॉरिटानिया के प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने का मौका दिया। पर उनका बयान शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हाथों से इशारा करके मॉरिटानिया के प्रेसिडेंट को अपनी बात जल्द खत्म करने का संकेत दिया। पर इसके बाद भी मॉरिटानिया के प्रेसिडेंट अपने देश कीसमस्याओं के बारे में बताते रहे। शायद वो अमेरिका से कुछ मदद चाहते होंगे। और तब राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपना सिर हिलाते हुए हाथों से दूसरी बार इशारा किया और इस बार उनकी झुंझलाहट देखकर मॉरिटानिया के प्रेसिडेंट अचानक खामोश हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प किस तरह ग्लोबल साउथ के साथ भेदभाव करते हैं। जबकि हमारे पीएम इन्हीं देशों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनके सुख-दुख का ख्याल करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के उन मुद्दों को भी उठाते हैं, जिसे पश्चिमी देश आजतक अनदेखा करते आए हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ वार पर जग हंसाई-दुनियाँ से दुश्मनी की नौबत आई-नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चांस घटाई ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, अपनी नीतियों व बयानों से सुर्खियों में रहे है अमेरिकी फर्स्ट के लिए कमर कसी- दुनियाँ के देशों की व्यापार नीति फंसी-ब्रिक्स देशों,यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी देशों,ग्लोबल साउथ, छंटनी के लिए फेरबंदी कसी मेरे विचार से सबसे कठिन स्थिति होगा।

सम्पादकीय...

पर्यावरण से खिलवाड़

ग्रेट निकोबार द्वीप, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, अपनी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, होने के साथ-साथ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुछ समय पहले नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित रु. 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ने इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार, पर्यटन और सामरिक महत्व का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविदों, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को नीति आयोग ने 2021 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य इस द्वीप को एक आर्थिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। परियोजना के तहत 16,610 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें से 130.75 वर्ग किलोमीटर प्राचीन वन क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों ने इसे विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। ग्रेट निकोबार द्वीप 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह द्वीप 1,767 प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता का घर है, जिसमें 11 स्तनधारी, 32 पक्षी, 7 सरीसृप और 4 उभयचर प्रजातियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में स्थानिक हैं। परियोजना के लिए लगभग 9.6 लाख से 10 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी, जो द्वीप के प्राचीन वर्षावनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। गलाथिया खाड़ी, जहां ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है, लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापोड पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2021 में गलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य को डिनोटिफाई कर दिया गया, जो भारत के राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण योजना (2021) के विपरीत है। यह कछुओं और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि बंदरगाह निर्माण से होने वाला प्रदूषण, ड्रेजिंग, और जहाजों की आवाजाही उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करेगी। द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परियोजना से इनके पारंपरिक क्षेत्रों का 10वां हिस्सा प्रभावित होगा, जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीविका पर खतरा मंडराएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से इन जनजातियों में रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है।

ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान-सुमात्रा फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो भूकंप और सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन में भूकंपीय जोखिमों को कम करके आंका गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजना के लिए साइट-विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन नहीं किए गए। यह एक बड़े पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है। परियोजना के लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। लेकिन ये क्षेत्र निकोबार की जैव विविधता से कोई समानता नहीं रखते। यह पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में असमर्थ है। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन दस्तावेजों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल हवाई अड्डे का सामरिक महत्व हो सकता है, न कि पूरी परियोजना का। पारदर्शिता की यह कमी परियोजना की वैधता पर सवाल उठाती है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने परियोजना को «पारिस्थितिक और मानवीय आपदा» करार दिया है। पर्यावरणविदों और नागरिक समाज संगठनों ने इसे जैव विविधता और आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 2023 में परियोजना को पर्यावरण और वन मंजूरी की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पारदर्शी और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, आदिवासी समुदायों के साथ उचित परामर्श और भूकंपीय जोखिमों का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। इसके साथ ही, परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता की पुन: समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में हाल ही में शुरू हुआ विशाखापत्तनम का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पहले से ही वैश्विक व्यापार में योगदान दे रहा है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि परियोजना क्षेत्र को सीआरजेड 1ए क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। आदिवासी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भूकंपीय जोखिमों के लिए साइट-विशिष्ट अध्ययन किए जाएं। निकोबार के भीतर ही प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान दिया जाए। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसे बचाने के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। भ्रामक तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर करेंगे।

धर्मांतरण का षड्यंत्र

धर्म परिवर्तन से समाज, संस्कृति, लोगों का आचरण, आचार, विचार, व्यवहार और सभ्यता सब कुछ बदल जाते हैं। पुरानी सभ्यताएं लुप्त हो जाती हैं और नई सभ्यता आ जाती है। किसी भी व्यक्ति का किसी धर्म को मानना या न मानना उसका अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। आप को भी जो धर्म सही लगता है आप उसका पालन करें। भारत में सभी को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अध्याय-3 में कहा है कि स्वधर्म भले ही कमजोर क्यों न हो, दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि जैसे एक पेड़ अपनी जमीन में ही सबसे अच्छा फल देता है, वैसे ही इंसान अपने मूल धर्म में ही सच्ची शांति और आत्म संतोष पा सकता है। भारत में धर्म परिवर्तन की साजिशें आज भी जारी हैं। इस्लामी जेहादियों द्वारा बड़े पैमाने पर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन की भयावहता पर उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा यानि जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जनमानस सोचने को विवश है कि हिन्दुओं के देश में यह क्या हो रहा है। वैसे तो देश में धर्मांतरण कोई नई बात नहीं। मुगलों के आने के साथ ही तलवारों के दम पर धर्मांतरण का षड्यंत्र शुरू हो गया था। आज जो पीढ़ियां हमें दिखाई देती हैं, वे उसी धर्मांतरण का परिणाम है। धर्मांतरण की साजिशों में जेहादियों को वर्ष 2047 तक गजवा-ए-हिन्द का सपना दिखाई देता है और जेहादियों का इरादा भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के मधपुर में छांगुर बाबा की करोड़ों की आलीशान कोठी मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब वहां गर्दा और गुब्बार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन सराहनीय है। क्योंकि धर्म परिवर्तन की साजिशों को विफल बनाना जरूरी है। अब प्याज के छिल्कों की तरह परत-दर-परत छांगुर बाबा की सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह जमालुद्दीन को तीन वर्षों में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। 200 करोड़ के लेन-देन की पुष्टि हो चुकी है। जबकि 300 करोड़ का लेन-देन नेपाल के माध्यम से हुआ। एक पूरा गैंग अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने में लगा हुआ था। हिन्दू धर्म की मान्यताओं को पाखंड बताकर और प्रलोभन देकर हिन्दुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था। अलग-अलग धर्मों की लड़कियों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए अलग-अलग रेट भी तय कर रखे थे। वैसे, इसके पहले तक इश्क, मोहब्बत का नाम देकर और इसे नितांत निजी मामला मानकर समाज, पीड़ित परिवार और बेटियों को उनके भरोसे ही छोड़ देता आ रहा था लेकिन पहली बार देश के आम लोगों ने जाना कि यह षड्यंत्र कितना गहरा और भयानक है। इसे आज नहीं समझा गया तो यह आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी और जो मुगल नहीं कर पाए, वह भविष्य में संभव हो सकता है।

आज ही कश्मीर, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों की जनसांख्यिकी में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और इसका असर सरकार के निर्णयों, समाज के व्यवहार और देश विरोधी घटनाओं से देखा जा सकता है।

लव जेहाद को लेकर अब गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। अब इसकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। इस्लामी जेहादी ही नहीं ईसाई मिशनरियां भी कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई हैं। कुछ वर्ष पहले केरल की लड़कियां सामने आई थीं और उन्होंने इस बात का पर्दाफाश किया था कि किस तरह धोखे से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। केरल की पढ़ी-लिखी युवतियां और युवक दुर्दांत आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया तक पहुंच गए थे। जहां उनका जीवन नरक बन गया था। हैरानी की बात तो यह है कि छांगुर बाबा के षड्यंत्र में हिन्दू से मुस्लिम बनी युवतियां भी संलिप्त हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले वर्ष 2021 के मूल धर्मांतरण विरोधी कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया है और आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। 2017 से कई भाजपा शासित राज्यों ने विवाह, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए या संशोधित किए हैं। ये उपाय स्पष्ट रूप से «लव जिहाद» का मुकाबला करने के उद्देश्य से हैं-एक सिद्धांत, जिसे मुख्य रूप से हिंदुत्व समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो आरोप लगाता है कि अंतर-धार्मिक विवाह संभावित जबरन धर्मांतरण के स्थल हैं। देश के 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। इस कानून की वजह से ही छांगुर बाबा के करोड़ों के साम्राज्य पर बुलडोजर चला। पंजाब और अन्य राज्यों से भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है। अब समय आ गया है कि देश के हिन्दू और सिख देश विरोधी साजिशों से सतर्क रहें। परिवारों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना और बच्चों में अच्छे संस्कार धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना समाज की जिम्मेदारी है। समाज ऐसे लोगों तक अपनी पहुंच बनाए जो आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के लिए धर्म परिवर्तन करने को ललायित हो सकते हैं। धर्माचार्यों को भी समाज में अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी।

फिर भारी बरसात बनी आफत

कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि मानसून शुरू होते ही आफत आ जाती है। कहीं बाढ़, कहीं जल भराव। इस बार तो हद हो हो गई। कहते हैं न कि जब अपने पर बीतती है तब मालूम पड़ता है। घर और आफिस में बैठकर तो हम अखबार, टीवी से न्यूज देख लेते हैं तो हमें लगता है बरसात हो रही है तो कुछ न कुछ तो होगा। जब मैं 9 तारीख को मौर्य होटल में एक फंक्शन अटेंड कर रही थी वहां खाना था परन्तु खाया नहीं कि बच्चों के साथ खाऊंगी, 8 बजे होटल से बाहर निकली तो देखा इतना ट्रैफिक जाम, बरसात हो रही थी, गाड़ी चल ही नहीं रही थी। भूख से बुरा हाल हो रहा था। बेटे बार-बार फोन कर रहे थे, कहां पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसे ट्रैफिक में फंसी हूं तो आदित्य ने कहा कि मम्मी फोन पर रील देखो, समय पास होगा। आकाश फोन कर रहा था कि आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी अर्जुन फोन कर रहा था। सब जगह पानी ही पानी था, जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। सबसे अफसोस की बात थी कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था कि गाड़ियों को सिस्टम से निकाल सके। एम्बुलैंस फंसी हुई थी, बेचारा ड्राइवर सायरन बजा रहा था। रास्ता साफ हो तो आगे बढ़े। जल्दी-जल्दी में आगे जाने की होड़ में गाड़ियां फंस रही थीं। पंजाबी बाग पुल पर 1 घंटा फंसी रही। फिर अपने आफिस के सामने यू टर्न पर 40 मिनट लग गए, वो भी हमारे सिक्योरिटी वालों ने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया। सामने बिल्डिंग दिख रही थी और गूगल मैप 40 मिनट दिखा रहा था। आखिरकार साढ़े 11 बजे मैं घर पहुंची, बच्चों और मैंने चैन की सांस ली। खाना साढ़े 11 बजे खाया, 1 बजे तक सो नहीं सकी। घर आकर मन ही मन सोच रही थी कि कई ऐसे लोग फंसे होंगे जिनको बाथरूम जाने की जल्दी होगी, कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होगा। रात को नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह जैसे ही अखबार खोला सामने खबर थी, एक युवक साइकिल पर था वो गड्ढे में गिर गया, उसका साथी बहुत चिल्लाया परन्तु किसी ने नहीं सुना। गौरव नाम का लड़का जो बिहार से दिल्ली घूमने आया था अपने चाचा के पास। सड़क पर पानी लबालब भरा होने की वजह से पूरी तरह ट्रैफिक जाम था। उसे अंदाजा नहीं था कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर खुले नाले का मैन होल है और उस पर पत्थर नहीं लगा हुआ था, उसमें गिर गया और लाश कई घंटों बाद मिली। मेरी ममता तड़फ उठी। किसी मां का लाल प्रशासन की लापरवाही से संसार से चला गया। क्या देश में महानगरों का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है? इस सवाल का उत्तर कुछ घंटों की बारिश में डूबते महानगरों को देखकर मिल रहा है। कुछ दशक पहले मानसून की वर्षा रिमझिम-रिमझिम पूरा सप्ताह होती थी, तब जल भराव नहीं होता था लेकिन आज वर्षा का पैटर्न बदल चुका है। कुछ घंटों की वर्षा से ही जलथल एक हो जाता है। बड़े-बड़े वादों पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था भी बदल गई है और जो लोग बारिश की वजह से जाम में घंटों फंसते हैं, उनकी तकलीफ और दर्द को समझना जरूरी है। महानगर और छोटे-बड़े शहर झील बन जाते हैं, कारें तैरने लगती हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण लगातार आबादी का बढ़ता बोझ और शहरों का बेतरतीब और अनियंत्रित विकास है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो.: 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/30862)

नई दिल्ली (अजय कुमार चौधरी) इंदिरा भवन मे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष श्री Rahul Gandhi से झारखंड के कांग्रेस सांसदों, मंत्रियों और विधायकों ने मुलाकात कर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। छाया-इंदजीत सिंह

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल आज करेंगे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एडीईटीआईई (अदिति) की लॉन्चिंग

पानीपत। स्थानीय आर्य पीजी कॉलेज सभागार में आज प्रातः10 बजे केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा मंत्रालय की योजना एडीईटीआईई (अदिति) मंगलवार को लॉन्च करेंगे। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी, एसीएस ऊर्जा विभाग ए. के. सिंह और ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। इसी को लेकर अक्षय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉक्टर प्रियंका सोनी ने एडीसी डॉक्टर पंकज यादव के साथ स्थानीय आर्य कॉलेज परिसर का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विदित रहे कि यह एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम) को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत, एमएसएमई को करोड़ों रुपये तक के ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। एडीसी डॉ पंकज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एमएसएमई को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम मंगलवार को प्रात 9 बजे शुरू किया जाएगा जिसमें एमएसएमई से जुड़े लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पानीपत सहित आसपास के जिलों के एमएसएमई से जुड़े लोगों और औद्योगिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है।

अमेरिका से समझौते में भारत को हितों पर अडिग रहने की सलाह, जीटीआरआई ने मसाला डील पर चेताया

नई दिल्ली । अमेरिका के बढ़ते दबाव के बावजूद भारत को अपने हितों के प्रति दृढ़ रहने की जरूरत है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया कि भारत को अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौता करने से बचना चाहिए। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दबाव में व्यापार समझौता करने से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। खासकर तब जब ऐसे समझौते अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के बाद टिक न पाएं। जीटीआरआई ने कहा कि ट्रंप की आक्रामक व्यापरिक धमकियां अब विश्वसनीयता खो रही है। तीन महीने से ज्यादा समय से जारी दबाव के बावजूद, केवल दो देश, युनाइटेड किंगडम और वियतनामस अमेरिका की एकतरफा व्यापार शर्तों पर सहमत हुए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों ने इन शर्तों का विरोध किया है। इसे जीटीआरआई ने 'MASALA डील बताया है, जिसका मतलब है मुचुअली एग्रीड सेटेलमेंट्स अचीव्ड फ्रू लेवेलारज्ड आर्म ट्विस्टिंग, यानी दबाव डालकर आपसी समझौते हासिल करना। रिपोर्ट में कहा गया कि इन समझौतों के तहत आमतौर पर अन्य देशों को अमेरिका से पारस्परिक रियायतें लिए बिना टैरिफ में कटौती करनी होती है, अमेरिकी वस्तुओं की खरीद की गारंटी देनी होती है। साथ ही वाशिंगटन को भविष्य में अतिरिक्त टैरिफ लगाने की गुंजाइश भी छोड़नी होती है। इन शर्तों को लागू करने में सीमित सफलता मिलने के कारण, ट्रम्प प्रशासन ने दंडात्मक उपाय अपनाए हैं। 7 जुलाई को, अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। कुछ ही दिनों बाद, 12 जुलाई को, यूएस ने यूरोपीय संघ और मेक्सिको से आयातित उत्पादों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी, जबकि इन देशों के साथ बातचीत अभी भी जारी है। जीटीआरआई रिपोर्ट ने भारत से आग्रह किया कि उसे समझना होगा कि वह अकेला देश नहीं है जो इस तरह के दबाव का सामना कर रहा है। अमेरिका इस समय 20 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और 90 से ज्यादा देशों से रियायतें मांग रहा है। हालांकि, अधिकांश लोग इसका विरोध कर रहे है, क्योंकि उनका मानना है कि ये मसाला सौदे राजनीति से प्रेरित हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई स्थायी निश्चितता प्रदान नहीं करते है।

इस्राइली सैटकॉम स्पेस मार्केट में हाथ आजमाएगी भारतीय एयरोस्पेस कंपनी, सैन्य बलों के साथ किया अनुबंध

गुरुग्राम। भारतीय एयरोस्पेस कंपनी- रंगसन एयरोस्पेस अब वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत इस्राइली सैटकॉम स्पेस मार्केट में प्रवेश करने जा रही है। इसके अलावा, कंपनी कोर एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विस्तार करने की तैयारी में है। यह कंपनी एनआर ग्रुप का हिस्सा है, जो साइकिल अगरबत्ती बनाती है। ये अगरबत्ती अब देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप विभिन्न देशों में भी निर्यात की जाती है। कंपनी का अनुमान है कि अगले दो-तीन वर्षों में निर्यात उसके कुल राजस्व का 60 फीसदी पहुंच जाएगा, जो अभी 50 फीसदी है। कंपनी अब पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व एशिया में विस्तार करना चाहती है। एयरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ने के लिए कंपनी ने बंगलूरू में अपनी विस्तृत आरएंडडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) केंद्र स्थापित किया है। कंपनी सैटकॉम और टाटालिंक सहित संचार के क्षेत्र में काम कर रही है। ये हवाई थर्मल प्रबंधन समाधान प्रदान करती है, जो मिसाइलों, ड्रोन, यूएवी, विमान, हेलिकॉप्टर, पनडुब्बियों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शीतलन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वक्त रंगसन

का अनुबंध डीआरडीओ, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और इसरो के साथ कई वैश्विक एयरोस्पेस कंपनियों के साथ है। किसी कंपनी में सीएसआर अब आया है। साइकिल अगरबत्ती कंपनी की ओर से 100 दिव्यांग बालिकाओं का स्कूल चलाया जा रहा है। अपने कर्मचारी के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी उठाती है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री कोष में एक करोड़ से अधिक की मदद की थी। अब कंपनी की ओर से ऑनलाइन पूजन सामग्री उपलब्ध कराने पर अधिक जोर है। एस्ट्रो पूजा डॉटकॉम के नाम से कंपनी पूरे विश्व में काम कर रही है। 75 साल पहले पत्नी के गहने व बचत के रुपयों से स्टार्टअप शुरू करने वाले एन रंगा ने अगरबत्ती का काम शुरू करते वक्त यह नहीं सोचा होगा कि उनकी कंपनी देश-विदेश में परचम लहराएगी। एन रंगा ने साइकिल अगरबत्ती को ही अपना कारोबार बना दिया। एक हजार रुपये से शुरू हुई कंपनी का टर्नओवर 1,500 करोड़ पहुंच चुका है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अर्जुन रंगा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में बताया, एनआर ग्रुप में छह कंपनियां हैं।?हमारे पास 500 से अधिक सुगंधों का पोर्टफोलियो है। एन रंगा राव एंड संस एक्सपोर्ट्स एनआर समूह की कंपनियों का निर्यात विभाग है, जो 50 से अधिक देशों में अपने उत्पादों की आउटसोर्सिंग का काम संभालता है। कंपनी की निष्कर्षण सुविधा मैसूर के पास स्थित है, जहां सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले रजनीगंधा फूल की खेती की जाती है।

हरियाणा विज़न 2047 दस्तावेज के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित

चंडीगढ़ । स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा हरियाणा के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विज़न 2047 दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले वर्षों में हरियाणा विकास और नवाचार के नए प्रतिमान स्थापित करे। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विज़न दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी और व्यापक बनाने के लिए जन परामर्श सर्वेक्षण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएँ सीधे सांझा कर सकते हैं, जो इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ का हिस्सा बनेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल का लिंक एनआईसी द्वारा बीएमएस, वित्त विभाग, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सभी उपायुक्तों और हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वेबसाइट पर सांझा किया जाएगा। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने मूल्यवान सुझाव इस जन परामर्श सर्वेक्षण में शामिल करने की कृपा करें।

हीमोफीलिया रोगियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से आज हीमोफीलिया रोगियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनके निवास स्थान पर मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में फैक्टर-8 और फैक्टर-9 की लगातार कमी को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया तथा जीवन रक्षक इन दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को इस वर्ष के बजट (2025-26) में हीमोफीलिया एवं थैलेसीमिया रोगियों के लिए घोषित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शीघ्र लागू करने का भी निवेदन किया, ताकि रोगियों को आर्थिक सहारा मिल सके। प्रतिनिधिमंडल में कैथल से राकेश यादव, यमुनानगर से विष्णु गोयल, रोहतक से अजय शर्मा, फतेहाबाद (भुना) से जोगिंदर सेठी, तथा कुरुक्षेत्र से सुखबीर समेत अनेक लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस विषय पर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने की बात भी कही।

ताइवान-वियतनाम की कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, यूपी-बिहार में अपार अवसर; निर्यात में यूएस पहली पसंद

नई दिल्ली। ताइवान और वियतनाम की कंपनियां भारत के गैर-चमड़ा फुटवियर क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के चेयरमैन आरके जालान ने रविवार को बताया, इन देशों की कंपनियों के निवेश को सुगम बनाने के लिए सरकारी समर्थन बेहद जरूरी है, ताकि वे अपनी विनिर्माण सुविधाओं के लिए इन वस्तुओं का देश में आसानी से आयात कर सकें। उन्होंने कहा, ये दोनों देश वैश्विक फुटवियर क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं। वियतनाम फुटवियर के निर्माण और निर्यात का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है। ताइवान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए फुटवियर के डिजाइन, विकास और उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। जालान ने कहा, सरकार को उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात बढ़ाने के लिए बजट में घोषित फुटवियर एवं चमड़ा क्षेत्रों के लिए केंद्रित उत्पाद योजना शुरू करनी चाहिए। इस योजना से गैर-चमड़े के गुणवत्ता वाले फुटवियर के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन क्षमता, कलपुर्जा विनिर्माण और मशीनरी को समर्थन मिलेगी। कानपुर की कंपनी ग्रोमोर इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक यादवेंद्र सिंह सचान ने कहा, ताइवानी कंपनियां पहले ही तमिलनाडु की इकाइयों में निवेश कर चुकी हैं। उनके पास फुटवियर बनाने की सर्वोत्तम तकनीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में निवेश के अपार अवसर हैं, क्योंकि इन राज्यों में किफायती श्रम उपलब्ध है। जालान ने कहा, देश का निर्यात अच्छी दर से बढ़ रहा है और परिषद 2025-26 में सात अरब डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2024-25 में निर्यात 5.75 अरब डॉलर रहा था। 95.7 करोड़ डॉलर (20 फीसदी हिस्सेदारी) मूल्य के निर्यात के साथ अमेरिका भारतीय निर्यातकों के लिए शीर्ष गंतव्य रहा। इसके बाद ब्रिटेन (11 फीसदी) और जर्मनी का स्थान है। उन्होंने कहा, इस वर्ष निर्यात में करीब 18 फीसदी वृद्धि की उम्मीद है। जालान ने कहा, देश का निर्यात अच्छी दर से बढ़ रहा है और परिषद 2025-26 में सात अरब डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है।

थोक कीमतें जून में 0.13 प्रतिशत घटीं, खाद्य पदार्थों व ईंधन के सस्ता होने से 15 महीने के निचले स्तर पर

नई दिल्ली ।

भारत की थोक मुद्रास्फीति जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13फीसदी रह गई। यह अक्तूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। सरकार की ओर से सोमवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए गए। इससे पहले, मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर 0.39फीसदी पर आ गई थी। रॉयटर्स की ओर से कराए गए अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में जून में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि के साथ 0.52 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। थोक मुद्रास्फीति में 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति इस महीने 1.97फीसदी रही। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर जून में 3.38 फीसदी रही। मई में यह 2.02फीसदी थी। इस बीच, ईंधन और बिजली के मामले में मुद्रास्फीति पिछले महीने के 22.27 फीसदी के मुकाबले घटकर

2.65फीसदी रह गई। इससे पहले, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2025 में छह साल के निचले स्तर 2.82फीसदी पर आ गई थी। इसमें अप्रैल की तुलना में 34 आधार अंकों की गिरावट देखी गई थी। यह आंकड़ा फरवरी 2019 के बाद से दर्ज सबसे कम वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। थोक महंगाई दर में नरमी के बीच जून में कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट खाद्य पदार्थों की कीमतों में देखी गई। सब्जियों की मुद्रास्फीति जून में घटकर 22.65 फीसदी रह गई, जबकि मई में यह 21.62फीसदी थी। प्याज की मुद्रास्फीति घटकर 33.49 फीसदी रह गई, जो एक महीने पहले 14.41फीसदी थी।

वहीं, आलू की मुद्रास्फीति (-)32.67 फीसदी रही, जबकि मई में यह (-)29.42फीसदी थी। दालों की कीमतें (-)22.65 फीसदी रही, जबकि पिछले महीने यह 10.41फीसदी थी। वहीं अनाज की मुद्रास्फीति मई में 2.56फीसदी दर्ज की गई थी, जो घटकर 3.75फीसदी रह गई। इसके अलावा, देश में खुदरा मुद्रास्फीति मई 2025 में छह साल के निचले स्तर 2.82फीसदी पर आ गई। भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी अप्रैल की बैठक में, मूल्य दबावों में निरंतर नरमी का हवाला दिया था। एमपीसी ने मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी को इसका कारण बताया था। इसने वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति में और नरमी का अनुमान लगाया था। महंगाई कम होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

एमपीसी ने अपने वित्त वर्ष 26 के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4 फीसदी तक संशोधित किया, जो इसके पहले के 4.2फीसदी के अनुमान से कम है। तिमाही-वार अनुमानों से पता चला है कि पहली तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 3.6 फीसदी, दूसरी तिमाही में 3.9फीसदी, तीसरी तिमाही में 3.8फीसदी और वित्त वर्ष 26 की अंतिम तिमाही में 4.4 फीसदी रहने की उम्मीद है।

पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय का ज्वलंत मुद्दा एवं चिंतनीय विषय

चंडीगढ़ । हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि धरा के संरक्षण के लिए पेड़ वरदान है। इसी प्रकार संतुलित एवं सभ्य समाज के निर्माण के लिए बेटियों का बराबर सम्मान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन महत्वपूर्ण विषयों के प्रति पूर्णतया गंभीर है और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत कर देश वासियों से पौधारोपण में सहभागिता की अपील की। इसी तरह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की दूसरी बड़ी योजना है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने थी। इन दोनों अभियानों के प्रति जन-जन में चेतना आने वाले समय में संतुलित समाज एवं शुद्ध पर्यावरण की पोषक साबित होंगी। श्री बेदी आज जींद जिले के गांव छब्बी टेक सिंह में पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण करने उपरांत लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक करोड़ 50 लाख रूपये अनुदान देने की भी घोषणा की। श्री बेदी ने कहा कि महिला सम्मान के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए महिलाओं में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का होना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि विभागीय औपचारिकताएं एवं तकनीकी नॉर्म्स पूरा होने पर सभी कार्यों का निर्माण करवा दिया जाएगा। श्री बेदी ने नरवाना बस स्टैंड के नजदीक निजी संस्था द्वारा संचालित एक जिम का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आज के भौतिकवादी युग में जहां मानव जीवन में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में इस तरह के जिम एवं शारीरिक कसरत ही युवाओं और नागरिकों को सशक्त एवं स्वस्थ बनाने में मददगार हो रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। यह पहल न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम कदम है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन का संदेश भी देती है।

नई दिल्ली (अजय कुमार चौधरी)नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

छाया- इंद्रजीत सिंह

दिल्ली में लागू होगा एआई आधारित शिक्षा मॉडल, बांटे जाएंगे 21 हजार टैबलेट; शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को जागरण विमर्श में कहा कि पिछली सरकार ने दस वर्षों में शिक्षा को वोट बटोरने का औजार बनाने का काम किया गया था। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पिछड़ने का काम किया गया। दिल्ली के शिक्षा के मॉडल में कुछ कमरे और स्वीमिंग पूल बना देना मॉडल नहीं हो सकता। दिल्ली में सरकारी स्कूल एक हजार रह गए और निजी स्कूल बढ़कर 1700 हो गए। क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाई के तौर-तरीकों में पिछड़ गए। उन्होंने कहा, रेखा सरकार में एआई व तकनीक आधारित शिक्षा मॉडल लागू होगा। 37 हजार क्लास में 700 स्मार्ट बोर्ड थे। सभी सीएमश्री स्कूलों में 21000 स्मार्ट क्लास बनाएंगी। देश में एक बोर्ड पर्याप्त है इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीबीएसई से पढ़ाई होगी। इसलिए डीबीएसई को बंद करने का फैसला लिया गया है। 27 वर्षों से स्कूलों में अभिभावकों पर तरह तरह के आर्थिक बोझ लादे जाते हैं। सूद ने कहा कि नए एक्ट को दिल्ली कैबिनेट से स्वीकृति देकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। इसे नए वर्ष से लागू किया जाएगा। मातृ भाषा में कोई भी व्यक्ति बेहतर सोच सकता है इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा में मातृ भाषा में शिक्षा का प्राविधान किया गया है। साइंस ऑफ लिविंग में मिस्टिक सेंस की पढ़ाई नर्सरी से ही होनी चाहिए। अध्यात्म को भी शामिल किया जाएगा। 21 हजार टैबलेट बांटे जाएंगे। दिल्ली सरकार के पास पिछली सरकार के गलत प्रबंधन के कारण बजट का अभाव है। गरीब बच्चों की मदद के लिए सीएसआर के तहत मदद कीजिए। जल्द ही सरकार एक सीएसआर ट्रेल शुरू करेगी। एक वर्ष में पढ़ाई का तौर तरीका बदल कर दिखाएंगे। 12 दिल्ली विश्वविद्यालय को ग्रांट दिए। 16 कॉलेजों को पांच प्रतिशत ग्रांट दिल्ली सरकार देती है। स्कूल व कॉलेज में बगैर विवाद के पढ़ाई हो इस पर काम कर रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवासन ने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पीएमजेएवाई को लागू नहीं किया। यह एक योजना है जो देश भर के लोगों के दिल को टच किया है और बेहद सफल योजना है। एम्स में हमने मंगलसूत्र बेचकर इलाज कराते देखा है। दिल्ली में पीएमजेएवाई से एम्स में 13 हजार मरीजों का इलाज हो चुका है। एम्स के मल्टिव्द मोड में जाकर देखें कि एम्स में ढांचागत सुविधाएं कितनी बढ़ी हैं। दिल्ली में साइलोस नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में केंद्र, दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य कई एजेंसियों के अस्पताल अलग-अलग चलते हैं। सभी एजेंसियों के अस्पतालों के बीच एक रेफरल सिस्टम होना चाहिए। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों का गैप एनालिसिस करके दिया है। यदि उस गैप एनालिसिस की भरपाई कर दी जाए तो सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। अभी दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड आक्यूपेंसी कम है। किसी अस्पताल में वेंटिलेटर है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं हैं। केंद्र के अस्पतालों में 100 प्रतिशत या इससे ज्यादा बेड आक्यूपेंसी है। आईपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि आईपी विश्वविद्यालय में 42 हजार सीट पर दाखिले के लिए लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। इस वर्ष एक चैटबाट बनाया है ताकि छात्रों को आसानी से सूचनाएं मिल सकें। शोध के बगैर उत्कृष्ट नहीं कर सकते। शोध के लिए इकोसिस्टम बनाना होता है। नीति आयोग के साथ अटल इनक्यूबेशन शुरू किया है ताकि छात्र अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। महाराजा अग्रसेन तकनीकी शिक्षा समिति के संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि दिल्ली में एक काउंसलिंग सिस्टम हो इसके लिए वर्ष 2014 में एक नियम पास हुआ था। आईपी विश्वविद्यालय के शुल्क महंगे कर दिए गए।

लद्दाख में एलजी और हरियाणा-गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति

नई दिल्ली।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल और पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा

कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान; जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके

(सेवानिवृत्त) का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। ये नियुक्तियाँ उस तिथि से प्रभावी होंगी जिस दिन नए नियुक्त व्यक्ति अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। ये नियुक्तियाँ दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख संवैधानिक पदों पर फेरबदल का संकेत है। आशिम कुमार घोष, जिन्होंने वरिष्ठ शैक्षणिक पदों पर कार्य किया है और उच्च शिक्षा में अपने प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करेंगे। वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, पुष्पति अशोक गजपति राजू, गोवा में कार्यभार संभालेंगे। राजू ने अपने दशकों लंबे राजनीतिक जीवन में आंध्र प्रदेश और केंद्र दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जम्मू से भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता, लद्दाख में नई दिल्ली की प्रशासनिक उपस्थिति का नया चेहरा बन गए हैं। गुप्ता इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और पीडीपी-भाजपा गठबंधन काल के दौरान उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।

बिहार बना 'क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया', कुर्सी बचा रहे सीएम नीतीश, राहुल गांधी

नई दिल्ली। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं, विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। इन सबके बीच कानून व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है।

राहुल ने एक्स पर लिखा कि बिहार बना 'क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया' - हर गली में डर, हर घर में बेचैनी! बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल ने आगे लिखा कि हरू कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं - इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। व्यापारियों, राजनेताओं, वकीलों, शिक्षकों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर एक के बाद एक

"भाजपा मंत्री कमीशन खाने में, राहुल ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

अंजाम दी जा रही हत्या की घटनाओं ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पुलिस ने इन घटनाओं के लिए अवैध हथियारों और गोला बारूद की व्यापक उपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले 10 दिन में, व्यवसायी गोपाल खेमका, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार, 60 वर्षीय एक महिला, एक दुकानदार, एक वकील और एक शिक्षक सहित कई लोगों की हत्याओं ने चुनाव से पहले बिहार को दहला दिया है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में जनवरी से जून के बीच हर महीने औसतन 229 हत्याओं के साथ 1,376 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 2,786 और 2023 में 2,863 थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अवैध रूप से निर्मित या बिना वैध लाइसेंस के खरीदे गए आग्नेयास्त्रों के प्रसार और कारतूसों व गोला-बारूद की अनियंत्रित उपलब्धता ने हाल में हिंसक अपराधों में तेजी ला दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार लगातार हिंसक अपराधों, जिनमें आग्नेयास्त्रों से जुड़े अपराध भी शामिल हैं, के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, राज्य 2017, 2018, 2020 और 2022 में हिंसक अपराध दर में दूसरे स्थान पर रहा है।

दिल्ली के तीन स्कूलों को बम की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली।

दिल्ली के तीन स्कूलों में सोमवार को ईमेल से बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे पुलिस को प्रशांत विहार और द्वारका सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ स्कूलों के साथ-साथ चाणक्यपुरी स्थित एक अन्य स्कूल से बम की धमकी के बारे में कॉल आए। पुलिस दल तुरंत स्कूल परिसर की जांच के लिए पहुंच गए। इलाके की तुरंत तलाशी ली गई। स्थानीय पुलिस, खोजी कुत्ते और बम निरोधक दस्ते स्कूल पहुंचे और जांच की। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता कर रही है।

हम हैं जनता के, वे हैं अपने गुलाम - फातिमा पढ़ने से रोकने पर जम्मू सीएम

श्रीनगर। श्रीनगर में शहीद मजार पर फातिहा पढ़ने के बाद जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह दुखद है कि जो लोग खुद दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था है, उनके निर्देश के अनुसार, हमें यहां फातिहा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, हमें घर में नजरबंद रखा गया, जब गेट खुलने लगे, तो मैंने कंट्रोल रूम में इच्छा जताई कि मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूं, कुछ ही मिनटों में बंकर लगा दिए गए। आज, मैंने सूचित नहीं किया, उनकी बेशर्मी देखिए, उन्होंने आज भी रोकने की कोशिश की... उन्होंने हाथापाई भी की, पुलिस कभी-कभी कानून भूल जाती है, मुझे आज क्यों रोका गया, प्रतिबंध कल के लिए थे... वे खुद को अपना गुलाम समझते हैं, अगर हम हैं, तो हम लोगों के हैं... हम यहां तब आएंगे जब हमें लगेगा।

आंध्र प्रदेश में आम से लदा ट्रक पलटने से नौ लोगों की मौत, 11 घायल

नई दिल्ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि अन्नामय्या जिले के रेड्डीचेरुवु के पास एक आम से लदी लॉरी के एक मिनी ट्रक पर पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई और ग्यारह अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार देर रात अन्नामय्या जिले के पुल्लमपेट मंडल के रेड्डीचेरुवु कट्ट के पास आम से लदी एक लॉरी के पलट जाने से नौ लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में आम से लदी एक लॉरी के पलट जाने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यह घटना रविवार रात जिले के पुल्लमपेट मंडल के रेड्डीचेरुवु कट्ट के पास हुई। आम

से लदे ट्रक पर 20 से ज्यादा लोग सवार थे। रात में जब यह हादसा हुआ, तब पीड़ित राजमपेट से रेलवे कोडूरु जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना रविवार रात लगभग 9:30 बजे हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, यह तब हुआ जब लॉरी का पिछला पहिया रेत में फंस गया और संतुलन खोकर एक मिनी ट्रक पर गिर गया। इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि रविवार देर रात जब यह हादसा हुआ, तब पीड़ित राजमपेट से रेलवे कोडूरु जा रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि घायलों को उचित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार मृतकों के परिवारों की पूरी मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चंद्रबाबू नायडू के साथ, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी लॉरी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने रविवार रात हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

पंजाब में बेअदबी के खिलाफ बिल को मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, विधानसभा में पेश

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट में बेअदबी बिल को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद बिल को विधानसभा में पेश किया गया। सीएम मान ने बेअदबी को लेकर बिल पेश किया। पंजाब में बेअदबी करने वालों को सजा दिलाने के लिए अभी कोई सख्त कानून नहीं है।

इस कानून से धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद मिलेगी। पंजाब में लंबे समय से बेअदबी कानून की मांग चली आ रही है। बेअदबी के मामलों में विशेष अदालतें गठित की जा सकेंगी। वहीं बेअदबी के दोषियों को पैरोल नहीं मिलेगा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब से वैसे पानी की मांग की जाती है, लेकिन जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो राजस्थान और हरियाणा पानी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अब जब हिमाचल में बारिश अधिक हो रही है और सभी डैम में अधिक पानी आ रहा है तो हरियाणा ने 6100 क्यूसेक से अधिक पानी लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार को पत्र लिखा गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी उनका ऐसा ही एक पत्र लिखा गया है। गोयल ने कहा कि सभी बांधों को पक्का किया गया है और नदियों की सफाई करवाई गई है। विधायक राणा इंदर प्रताप यह प्रस्ताव लेकर आए थे, जिस पर बाढ़ की रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, उस संबंध में सरकार से जवाब मांगा गया था।

सीजेआई बीआर गवई इंफेक्शन के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

नई दिल्ली।

भारत के सीजेआई बीआर गवई को इन्फेक्शन के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के सोर्स के मुताबिक, सीजेआई की हालत सुधार हो रहा है। उन्हें एक-दो दिन में अस्पताल छुट्टी मिल जाएगी। 12 जुलाई को हैदराबाद की यात्रा के दौरान सीजेआई की तबीयत बिगड़ी थी।

समाज को ऐसे लोगों की जरूरत, जो सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर करें : गडकरी

नागपुर।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोक प्रशासन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के खिलाफ अदालती मामले दायर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नागपुर में स्वर्गीय प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि अदालती आदेश से ऐसे काम हो सकते हैं जो सरकार भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करें। इससे

राजनेताओं में अनुशासन आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के मंत्री भी वह काम नहीं कर सकते जो अदालती आदेश से हो सकता है। लोकप्रिय राजनीति राजनेताओं और मंत्रियों के आड़े आती है। गडकरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुशल संगठक के रूप में सम्मानित किए गए लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसी कई कानूनी लड़ाइयाँ लड़ीं। देश में सड़क नेटवर्क में क्रांति लाने के लिए जाने जाने वाले भाजपा नेता ने कहा कि कुशल संगठकों ने शिक्षा क्षेत्र में गलत सरकारी फैसलों के खिलाफ कई अदालती मामले दायर किए और कई मौकों पर सरकार को अपने फैसले वापस लेने के लिए मजबूर भी किया। इससे पहले गडकरी ने रूस-यूक्रेन और इजराइल-ईरान युद्धों का हवाला देते हुए कहा कि महाशक्तियों की तानाशाही और निरंकुशता के कारण समन्वय, आपसी सद्भाव और प्रेम खत्म हो रहा है और दुनिया भर में संघर्ष का माहौल है। भारत को दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देने वाली बुद्ध की भूमि बताते हुए गडकरी ने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की समीक्षा और विचार-विमर्श के बाद भविष्य की नीति निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि ये संघर्ष ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां विश्व युद्ध 'कभी भी' छिड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध से संबंधित तकनीकी प्रगति भी मानवता की रक्षा करना कठिन बना रही है।

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार को सराहा

हरियाणा के सीएम ने स्वामी कल्याण देव को किया नमन

मुजफ्फरनगर।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी कल्याण देव का जीवन समाज को शिक्षित करने और कुरीतियां मिटाने के लिए समर्पित रहा। उनके द्वारा जो अच्छे कार्यों की शुरुआत की गई थी, उसे शुकदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद पुरी निष्ठा और समर्पण से आगे बढ़ा रहे हैं।

सोमवार को स्वामी कल्याण देव की 21वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौराणिक तीर्थनगरी शुकतीर्थ में पहुंचकर शिक्षा ऋषि वीतराग स्वामी कल्याण देव को नमन किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही प्राचीन वट

वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही पूजन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीन सदी के युग दृष्टा स्वामी कल्याणदेव ने समाज को शिक्षित और संस्कारित बनाने में जो योगदान दिया, वह अतुलनीय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के मंदिरों की न केवल नींव रखी, बल्कि सैकड़ों विद्यालय और कालेज बनवाकर आने वाली पीढ़ी को संवारने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि शुकतीर्थ पावन भूमि है, यहां पर ही पांच हजार साल पूर्व शुकदेव मुनि ने दुनिया में सबसे पहली बार राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण कराया, मैं भी इस भूमि पर आकर धन्य हो गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुकतीर्थ विकास परिषद का गठन करने के साथ ही यहां के सुंदरीकरण को लेकर जो प्रयास किए हैं, वह सराहनीय हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उपासना का महीना है, सभी कावड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उनकी शुभकामना है।

बिहार चुनाव से पहले मायावती का तंज: नीतीश की घोषणाएं केवल वोट बटोरने का हथकंडा

लखनऊ।

बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया रोजगार संबंधी वादों को महज बयानबाजी और चुनावी छलावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घोषणाएं बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए की गई हैं और राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति की राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच, संभवतः लोगों का ध्यान बांटने के लिए, राज्य

में एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव बाद सरकार बनने पर अगले पाँच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में लोगों को हकीकत से दूर, उनके अनुभवों के आधार पर, 'अच्छे दिन' जैसी जुमलेबाजी व चुनावी छलावा ज्यादा लगता है। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे, दावे, घोषणाओं व छलावों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था व कार्यकलापों आदि को लेकर इनके चाल, चरित्र व चेहरे आदि को जनता भलीभाँति जानती है, फिर भी अपनी छल व छलावा की राजनीति की आदत से मजबूर ये विरोधी पार्टियाँ चुनाव से पूर्व इस प्रकार के अनेकों लोक लुभावने वादे करने में ज़रा भी नहीं डरती व घबराती हैं। इसी क्रम में बिहार की वर्तमान गठबंधन सरकार का नौकरी व रोजगार का वादा इनके अन्य वादों से ज्यादा मेल खाता है, जो जनता वास्तव में अब तक के उनके अनुभव के आधार पर जानती भी है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने कहा, "निश्चय ही बिहार की जनता सोच-समझकर गरीब व सर्वजन हितैषी सरकार चुनेगी। बसपा प्रमुख ने चुनाव में गड़बड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा, "बशर्ते कि चुनाव बाहुबल, धनबल तथा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मुक्त पूर्णतः स्वतंत्र व निष्पक्ष हो तथा सभी गरीबों, मजदूरों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को वोट करने का सही से मौका मिले।" उन्होंने उम्मीद जताई, "निर्वाचन आयोग इसका पूरा ध्यान जरूर रखेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल हुआ, पीएम मोदी के आपत्तिजनक कार्टून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री मोदी और संघ पर आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हेमंत मालवीय ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने ये सब क्यों किया? हेमंत मालवीय की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह मामला बेशक अरुचिकर और खराब है, लेकिन यह अपराध नहीं है? यह निंदनीय हो

सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि यह बेशक अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। हेमंत ग्रोवर ने साल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान ये आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। इनके खिलाफ संघ कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने इंदौर के लसूड़िया थाने में मई माह में शिकायत दर्ज कराई। विनय जोशी ने आरोप लगाया कि हेमंत मालवीय ने कार्टून के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ने की कोशिश की। जोशी ने आरोप लगाया कि कार्टूनिस्ट ने भगवान शिव, पीएम मोदी, आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक कार्टून, वीडियो और फोटोग्राफ पर आपत्ति जताई और हिंदू धर्म और संघ की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने मालवीय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।